साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 26 जून-02 जुलाई 2023 वर्ष-9, अंक-11

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा

बिना ओटीपी-फिंगरप्रिंट के फेस स्कैन कर ई-केवाईसी करेंगे किसान

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम-किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है। केंद्र ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

राज्य ज्यादा तेजी से काम करेंगे

पीएम-किसान एक अभिनव योजना है जिसका लाभ बिना किसी बिचौलियों के केंद्र सरकार किसानों को दे पा रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को टेक्नालॉजी की मदद से ही लाभ देना संभव हो पाया है। इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है जो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार ने टेक्नालॉजी का उपयोग करके यह जो ऐप बनाया है उससे काम काफी सरल हो गया है। केंद्र ने सभी आवश्यक सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध करा दी हैं, अब राज्य ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो सभी हितग्राहियों तक हम पहुंच जाएंगे।

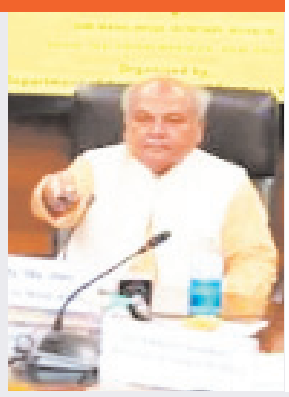

कोई परेशानी नहीं होगी

तोमर ने कहा कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम-किसान के काम तो आएगा ही और किसानों को कभी भी कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी।

अंतर्राज्यीय लायसेंस प्रक्रिया को सरल व सशक्त बनाया जाए

भोपाल। ई-नाम को और सशक्त बनाने अंतर्राज्यीय व्यापार को सुगम बनाया जाए। मंडी व्यापारियों के लिए लायसेंस प्रक्रिया को सरल करने पर कार्य करें। केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम की कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव फैज अहमद किदवई ने मंडी बोर्ड मुख्यालय में समीक्षा करते हुए यह बात कही। बैठक में प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड जीव्ही रश्मि सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ई-नाम की समीक्षा करते हुए किसानों द्वारा लाई गई कृषि उपज का प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण, सर्विस प्रोवाइडर, प्लेटफार्म टू प्लेटफार्म, ग्रिवेन्स रिड्रेसल मेकेनिज्म सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

किसानों को एक और सौगात | सीएम शिवराज ने की घोषणा

मध्यप्रदेश में किसान को साल भर में 12 हजार रुपए मिलेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को सौगात दी है। आगामी वर्ष से समर्थन मूल्य पर रबी सीजन (गर्मी) की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसभा का आयोजन बालाघाट में किया गया था। सीएम चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय प्रदेश की हालत सभी ने देखी है। सड़कें खराब थी। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई थीं। आवागमन में हिचकोले लगते थे। बिजली नहीं थी। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। 15 माह वाली कांग्रेस की सरकार ने कर्जमाफी का वादा कर किसानों को कर्जदार बना दिया। भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को 6 हजार रुपए सम्मान निधि देते हैं। हमने भी पहले 4 हजार रुपए दिए।

समर्थन मूल्य पर रबी की धान भी खरीदेगी सरकार

किसानों को अब छह हजार

अब 2 हजार रुपए बढ़ाकर 6 हजार रुपए देंगे। किसान को साल भर में 12 हजार रुपए मिलेंगे। हमने बालाघाट जिले की 3.25 लाख बहनों के खातों में 1000 रुपए डाले हैं। कांग्रेस ने तो बैगा, भारिया, सहरिया बहनों को मिलने वाली राशि भी बंद कर दी थी। बच्चों के लेपटॉप छीन लिए थे। संबल योजना बंद कर दी थी। कन्यादान योजना की राशि नहीं दी।

धान खरीदी बड़ा दांव

मध्य प्रदेश में अभी तक रबी यानी गर्मी के मौसम की धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती थी। यह धान महाकोशल अंचल में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। वहीं महाकोशल से लगे छत्तीसगढ़ की सरकार रबी की धान भी समर्थन मूल्य पर खरीदती है। ऐसे में महाकोशल के किसानों को अपनी धान औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है। इससे किसान तो परेशान होते ही हैं, मजबूरन उन्हें कम दाम लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस धान को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की लंबे समय से मांग चल रही थी। सरकार की घोषणा का इस जनजातीय बहुल बेल्ट पर असर पडऩे की संभावना है।

पशुओं में होने वाले वायरल डायरिया की जांच के लिए देश में बनी स्वदेशी किट

भोपाल। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान ने पशुओं में होने वाले वायरल डायरिया का पता लगाने के लिए जांच किट तैयार की है। यह पहली स्वदेशी किट है। यहां संस्थान के 23वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन आयुक्त अभिजीत मित्रा ने यह किट देश को समर्पित की। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह तकनीक किसी फर्म को हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद व्यवसायिक उत्पादन शुरू होगा। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि वायरल डायरिया अधिकतर गौवंशी पशुओं में फैलता है। यह वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे पशुओं को निमोनिया, बांझपन होता है। दूध का उत्पादन भी घटता है।

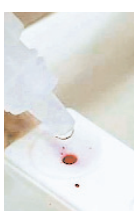

महाभियान में मिली सबसे बड़ी उपलब्धि, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कलेक्टर को दिया सर्टिफिकेट

सिर्फ 12 घंटे में 1552 सीमांकन...स्वर्ण अक्षरों में सतना का नाम दर्ज

सतना। जागत गांव हमार

प्रदेश और देश ही नहीं पूरे एशिया में जो कोई और नहीं कर सका,वह सतना ने कर दिखाया। सतना जिले के राजस्व अमले ने महज 12 घंटे में 1552 सीमांकन कर रिकॉर्ड बनाया और स्वर्णाक्षरों में सतना का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। इस उपलब्धि पर एक समारोह में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने सतना कलेक्टर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स-इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का विजेता होने संबंधी सर्टिफिकेट प्रदान किया। गत 20 मई को महज 12 घंटे में सतना जिले में किए गए 1552 सीमांकन प्रकरणों के निराकरण को एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किए जाने का उत्साह कलेक्ट्रेट में मनाया गया। इस अवसर पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि डॉ. हर्षित तिवारी ने सतना के रिकॉर्ड बनाने की आधिकारिक घोषणा करते हुए सतना कलेक्टर को सर्टिफिकेट दिया। इस महाभियान में जिलेभर के राजस्व अधिकारियों- कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई इस अवार्ड सेरेमनी में डॉ. हर्षित तिवारी ने बतौर कलेक्टर अनुराग वर्मा की लीडरशिप और जिले के समस्त राजस्व अमले के जज्बे और मेहनत की प्रशंसा की।

जिले के 730 हलकों में पदस्थ राजस्व विभाग के चौकीदार-कोटवार, पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एसडीएम-एडीएम ने फील्ड में अभूतपूर्व मेहनत की। रीडर- ऑपरेटर और भृत्यों ने कार्यालयीन काम निपटाने में अपना शत प्रतिशत दिया। जब हमने ये महाभियान शुरू करने का निर्णय लिया था, तब रिकॉर्ड बनाने का ख्याल भी नहीं आया था। हमने 1275 प्रकरणों का लक्ष्य लेकर सुबह से काम शुरू किया और देर रात तक यह संख्या 1552 पहुंच गई। यह सबकी मेहनत का परिणाम है।

अनुराग वर्मा, कलेक्टर, सतना

राजस्व के काम में सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया है, इसे एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में निराकृत करना तारीफ का काम है।

राजेश शाही, कमिश्नर

कलेक्टर की लीडरशिप में मिली इस बड़ी उपलब्धि ने हमें गौरवांवित किया है। प्रेरित किया है कि कोशिश कर रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं।

बीके मिश्रा, तहसीलदार

पिता ने शुरू की पालक, मूली की खेती, अब बेटा कर रहा बागवानी

रीवा के 'शुक्लाजी' के बगिया की सब्जी लाजवाब

रीवा। जागत गांव हमार

रीवा शहर के बीचों बीच ढेकहा बनकुइया रोड पर शुक्लाजी की बगिया है। 35 साल से शहर के लोग इस बगिया की सब्जी खा रहे हैं। आसपास के जिलों में भी यहां की सब्जी भेजी जाती है। 35 साल पहले शंभू प्रसाद शुक्ला ने यह बगिया लगाई थी। अब उनके बेटे अजय कुमार शुक्ला इसमें बागवानी कर रहे हैं। अजय ने एलएलबी किया है, लेकिन वकालत के साथ ही पिता की पुश्तैनी बगिया भी संवार रहे हैं। अजय ने मेहनत के बूते इस बगिया को हरी सब्जियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का रूप दे दिया है। सब्जी से होने वाली कमाई की बदौलत स्कूल समेत कई एकड़ कृषि भूमि खरीद चुके हैं। सब्जियों से होने वाली सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपए है, जो कि खेती की लागत और मजदूरों का मेहनताना निकालने के बाद मुनाफे के रूप में उन्हें मिलती है। पिता की पहल को रोजगार का साधन बनाने से लेकर इसे मुनाफे का व्यवसाय बनाने के दौरान अजय शुक्ला ने कई चुनौतियों को सामना किया है।

अजय शुक्ला कहते हैं कि मेरी बगिया में कुशवाहा समाज के लोग खेती करते हैं। मेरा मानना है कि बागवानी ऐसी होनी चाहिए कि क्यारी (परिया) के अंदर व मेढ़ दोनों जगह पौधे तैयार रहें। कुल मिलाकर बड़े खेत में छोटी-छोटी क्यारी के अंदर पालक व मेढ़ पर मूली के बीज का छिड़काव कर देते हैं। वहीं, एक किनारे गोभी की नर्सरी लगाते हैं। 15 दिन बाद नर्सरी का पौधा क्यारी की मेढ़ पर रोप देते हैं। ऐसे में एक ही खेत में 30 दिन में पालक, 50 दिन में मूली और 70 दिन के बाद गोभी की पैदावार मिल जाती है। ऐसे समय में जब खेती तकनीक पर आधारित हो गई है। पुराने तरीकों में बदलाव करना पड़ता है।

पुश्तैनी धंधा होने की वजह से धान और गेहूं की अपेक्षा सब्जियों की खेती में ही मेरा मन रम गया। मूली की बागवानी में मेहनत कम और कमाई ज्यादा होती है। हालांकि, अन्य वर्षों की अपेक्षा इस साल पैदावार कम है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि कृषि विभाग की ओर से अपेक्षाकृत मदद नहीं मिल रही है। मेरी बगिया में लगे मूली के पौधों में कीड़े लग गए थे। समय-समय पर दवा का छिड़काव किया, लेकिन राहत नहीं मिली है।

पालक की इन किस्मों की खेती

बघेलखंड में देशी पालक का बीज बोते हैं, जबकि विलायती पालक पहाड़ी क्षेत्रों में बोई जाती है। देशी पालक में पत्ते एक समान होते हैं। इन पत्तों की कटाई 15 से 20 दिन में होने लगती है। कुल 6 से 7 बार कटाई कर सकते हैं। यहां ग्रीन मडोरी, आल ग्रीन, हरिहर रिसर्च, मुलायम, हरित शोभा, पूसा हरित, पूसा ज्योति, बनर्जी जाइंट का बीज लगाते हैं।

इस तरह करें मूली की खेती

अजय कहते हैं कि विंध्य क्षेत्र में मूली की कई प्रजातियां लगाई जाती हैं। गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम के अनुसार बीज डालते हैं। गर्मी में सबसे ज्यादा पालक और सैंग्रो का बीज डालते हैं। वहीं, ठंडी में काटेदार पत्ते वाली मूली लगाते हैं। इसी तरह गर्मी में हिल क्लीन की बिजाई करते हैं, जबकि मूली की उन्नत किस्में पूसा हिमानी, पूसा देसी, पूसा चेतकी, पूसा रेशमी, जापानी सफेद उगा सकते हैं।

5 से 6 एकड़ में बागवानी की खेती

हम 5 से 6 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं। 1985 के आसपास पिता शंभू प्रसाद शुक्ला ने बागवानी की शुरुआत की थी। इसके बाद बागवानी से जुड़े हर कार्य में मैं हाथ बंटाता रहा। मेरा दूसरे नंबर का भाई पुनीत शुक्ला खेती व किसानी में लगा है, जबकि छोटा भाई सुधांशु शुक्ला स्कूल चलाता है। बागवानी से ही घर में छोटे से लेकर बड़े कृषि उपकरण खरीदे गए हैं। ढेकहा, करहिया और सांव गांव मिलाकर बागवानी से लेकर गेहूं और धान की बड़े स्तर पर खेती की जा रही है। फायदा हो या नुकसान अब इसे छोड़ नहीं सकता। इस बगिया से मेरे अलावा तीन से चार परिवार के लोग जुड़े हैं।

इन बातों को रखें ध्यान

- समय-समय पर निराई व गुड़ाई करने से कीड़े नहीं लगते। अगर कीड़े लगे तो दवा का छिड़काव करें।
- सब्जियों की खेती के लिए काली मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है।
- सब्जी लगाने से पहले ट्रैक्टर व कल्टीवेटर की मदद से दो बार खेत की जुताई कर दे, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए।
- खेत में छोटी-छोटी क्यारी तैयार करें। क्यारी के अंदर पालक का बीज लगाएं।
- पालक की क्यारी के मेढ़ पर 5-5 इंच की दूरी पर मूली का बीज डाले।
- एक कतार में मूली का बीज डालने से बाद में उसे उखाड़ने में किसान को आसानी रहती है।
- क्यारी में पानी लगाने के लिए नाली बना दे। पांच दिन में पौधा अंकुरित होकर दिखने लगेगा।
- विंध्य के मौसम में पालक की बारह मासी खेती होती है। मूली की खेती भी बारह मास कर सकते हैं।
- नर्सरी में तैयार गोभी के पौधे नाली के दोनों तरफ रोप देते हैं। ध्यान रहे गोभी के पौधे की आपस में दूरी डेढ़ से दो फीट रहनी चाहिए।
- जब खेत से पालक खत्म हो जाएगी, तब मूली निकलने लगेगी। इसके बाद गोभी की पैदावार मिलेगी।

किसानों के लिए लाभ का धंधा

बागवानी किसानों के लिए लाभ का धंधा है। विंध्य क्षेत्र का मौसम मूली, पालक और गोभी की फसल के लिए उपयुक्त है। बागवानी के लिए ऐसे खेत का चयन करें, जिसमें पानी नहीं रुकता हो। सिंचाई के पर्याप्त साधन हो यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। सब्जी की खेती में गोबर की खाद अच्छा उत्पादन व मुनाफा देती है। खेत तैयार करते समय गोबर की खाद डलवा दें।

डॉ. टीके सिंह, कृषि वैज्ञानिक, रीवा फल अनुसंधान केंद्र कुढुलिया

कृषि मंत्री कमल पटेल की अध्यक्षता में हुई मंडी बोर्ड संचालक मंडल की बैठक, बोले

प्रदेश की मंडी समितियों को अत्याधुनिक के साथ सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाए

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री-सह-अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कमल पटेल ने मंडी समितियों को अत्याधुनिक सर्व-सुविधायुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री मंडी बोर्ड के संचालक मंडल की 141वीं बैठक की अध्यक्षता मंडी बोर्ड मुख्यालय में कर रहे थे। उन्होंने कृषकों को कृषि उपज विक्रय के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पर संचालक मंडल ने सहमति दी। संचालक मंडल की बैठक में उपाध्यक्ष मंजू राजेन्द्र दादू, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, एमडी मंडी बोर्ड जीव्ही रश्मि, अपर आयुक्त पंजीयक बीएस शुक्ला, व्यापारी सदस्य अरुण सोनी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। मंडी बोर्ड संचालक मंडल की 141वीं बैठक में मंडी प्रांगण के बाहर कृषकों के हित में निर्मित कराई गई संरचनाओं को संचालन एवं संधारण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपने, राज्य शासन की पुनर्धनत्वीकरण नीति-2022 में प्रदेश में विद्यमान पुराने एवं अनुपयोगी रिक्त मंडी प्रांगण के उपयोजन, कृषि उपज मंडियों की अनुपयोगी भूमि निवर्तन संबंधी नीति निर्माण, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी समिति नियम-2009 संशोधित 2023 का अनुमोदन किया गया।

हेल्थ एटीएम स्थापित होगा

संचालक मंडल की बैठक में कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया में भूमि आवंटन/प्रांगण विस्तार, जबलपुर कृषि उपज मण्डी के नवीन मंडी प्रांगण प्रस्ताव, मंडी समितियों में किसानों के हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ एटीएम या हेल्थ चेकअप सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

ग्रामीण सड़कों का कार्य पूर्ण करे

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि स्वीकृत सडकों का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव से आदमपुर से सुरजाना की 5.08 किमी सडक़ को स्वीकृत करने को कहा।

राज्य मंत्री ने सात करोड़ की सडक़ों का किया भूमि-पूजन

अमरपाटन के हर गांव जुलाई तक हर घर पहुंचेगा नल से जल

भोपला। जागत गांव हमार

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामखेलावन पटेल ने कहा है कि बाण सागर सामूहिक ग्रामीण जल-प्रदाय योजना से सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में इस वर्ष जुलाई तक हर घर नल से जल पहुंचेगा। साथ ही इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर तक रामनगर क्षेत्र के खेतों में सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध होगा। राज्य मंत्री 7 करोड़ 28 लाख रुपए लागत से बनने वाली 7 पक्की सड़क के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि यह 7 पक्की सड़कें क्षेत्र की 13 पंचायतों की जीवन-रेखा होंगी। सड़कों के बनने से इन क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को सडक़ का कार्य नियत समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने नगर परिषद रामनगर में 2 करोड़ 16 लाख लागत के 19 विकास कार्य का भूमि-पूजन किया। इस राशि से वार्डों में नाली निर्माण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम पूरे किये जायेंगे। राज्य मंत्री ने अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खजूरी सुखनंदन एवं ग्राम भदवा में 2 सड़कों का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि अमरपाटन क्षेत्र में मैहर ढाबा से झिन्ना नाला तक करीब साढ़े 5 किलोमीटर सडक़ के मजबूतीकरण के लिए 21 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग ने मंजूर की है। जल्द ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

मध्यप्रदेश-राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में कर रहे निर्यात

हर साल 60 हजार किलो पैदावार, आमदनी भी 18 से 20 लाख रुपए तक, अपने गांव के नाम से सारस ब्रांड भी बनाया

आम से लाखों कमा रहे किसान बाग में कई पेड़ 100 साल पुराने

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के किसान संजय बघेल का परिवार पिछले 100 साल से आम की खेती कर रहा है। 100 साल पहले मात्र 5 आम के पेड़ से शुरू हुए इस बगीचे में अब एक हजार आम के पेड़ हैं। सिवनी जिला मुख्यालय से 16 किमी दूर सारसडोल गांव के किसान संजय बघेल पहले पारंपरिक खेती करते थे। पारंपरिक खेती में मेहनत, लागत अधिक और आमदनी कम थी। वह कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे ये अपने गांव से भी जुड़े रहे और आमदनी का जरिया भी तैयार कर सकें। इसी उद्देश्य से पांच साल पहले उन्होंने अपने पुश्तैनी बगीचे को व्यवसायिक रूप देना शुरू किया। देखते ही देखते इनके बगीचे में आम के पेड़ की संख्या में इजाफा होने लगा। पेड़ों की संख्या बढ़ी तो बगीचे का दायरा भी बढ़ता गया। पांच साल पहले जब व्यवसायिक स्तर पर संजय ने आम की खेती शुरू की तो मात्र 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी होती थी। एक सीजन के हिसाब से यह आमदनी काफी कम थी, लेकिन उन्होंने बगीचे का दायरा जैसे ही बढ़ाया आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ने लगी। अब 20 एकड़ में आम के करीब एक हजार पेड़ हो गए हैं। इनसे हर साल 50 से 60 हजार किलो आम की पैदावार हो रही है। साथ ही आमदनी भी 18 से 20 लाख रुपए तक हो रही है। इन्होंने अपने गांव के नाम से सारस ब्रांड भी बनाया है।

आम का पौधा ऐसे लगाएं

आम की रोपाई पौधे के रूप में की जाती है। आम का पौधा लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर व्यास वाला एक मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। मई महीने में गड्ढा खोद कर उनमें 30 से 40 किलो ग्राम प्रति गड्ढा गोबर की खाद मिटटी में मिलाकर डाल देते हैं। साथ ही 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफास पाउडर गड्ढे में भर दिया जाता है। अच्छी जल धारण क्षमता वाली बलुई व दोमट मिट्टी आम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जमीन का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। 10म10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। वहीं सघन बागवानी में इसे 2.5 से 4 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। गड्ढों में पौधों को लगाने से पहले गौमूत्र से उपचारित कर लिया जाता है।

2 साल तक पौधों की करें सिंचाई| आम के पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय बारिश का मौसम होता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक आम के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद दो साल तक नियमित सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए ड्रिप ऐरिगेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए। इससे पौधों को उतना ही पानी मिलता है, जितने की जरूरत उन्हें होती है।

खरपतवार का नियंत्रण करते रहें

आम के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौधों में खरपतवार का नियंत्रण प्राकृतिक विधि से किया जाता है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई पौध रोपाई के एक महीने बाद की जाती है। आम के पौधों में प्रारंभिक वर्ष में 8 से 10 गुड़ाई की जरूरत होती है। इसकी पहली गुड़ाई के बाद बाकी की गुड़ाई को 20 से 25 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। इसके पौधे में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जो इसके पौधों को नष्ट कर पैदावार को प्रभावित करते है। इन रोगों में आंतरिक विगलन, गमोसिस, तना बेधक, एन्थ्रेक्नोज, मैंगो हॉपर, पाउडरी मिल्ड्यू प्रमुख हैं।

आम में खर्रा व दहिया रोग का भी खतरा

खर्रा रोग एक कवक से होने वाली बीमारी है। इस रोग के लक्षण बौरों, पुष्पक्रम के डंठल, नई पत्तियों और फल आने के बाद फलों पर सफेद पाउडर के रूप में दिखता है। इसकी वजह से फूल खिलने से पहले गिर जाते हैं। इसका सीधा असर आम की पैदावार पर पड़ता है। घुलनशील गंधक पानी में मिलाकर या हेक्साकोनाजोल के 0.1 प्रतिशत घोल को प्रति लीटर मिलाकर छिड़काव करें।

कीट से ऐसे बचाएं

आम के बाग में जनवरी से लेकर मार्च तक जमीन से गुजिया कीट निकलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढक़र पत्तियों और बौर का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। इन कीटों की वजह से पत्तियों और बौर पर चिपचिपा पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे फफूंद बढऩे लगते हैं। अगर ये कीट पत्तियों और बौर पर दिखाई दें तो इनके प्रबंधन के लिए कार्बोसल्फान 25 ईसी का दो मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडक़ाव करते हैं।

गोबर खाद का करें इस्तेमाल

संजय अपने बगीचे में केवल गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर खाद के उपयोग से आम की मिठास से बढ़ जाती है और जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। सिर्फ बीमारियों से बचाव के लिए ही रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। गोबर खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती, मिट्टी के लाभकारी जीवाणुओं और केंचुओं के लिए बेहद फायदेमंद होती है। गोबर खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में केंचुओं की मात्रा तेजी से बढ़ती है, जिससे मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। गोबर की खाद में 50त्न नाइट्रोजन, 20त्न फास्फोरस व पोटेशियम पाया जाता है जोकि पौधों के पोषण के लिए जरूरी होता है।

बगीचे में पक्षियों को भगाने लगाए काकभगोड़े

संजय बघेल ने अपने बगीचे में सीमेंट की बोरी से काकभगोड़ा बनाए हैं, ताकि कोई भी पशु-पक्षी फल को नुकसान ना पहुंचा सकें। वहीं कांच की खाली बॉटल भी पेड़ से लटका दिए हैं। इसकी आवाज से पक्षी नहीं आते। आम की डालियों पर बोतल और इनसे टकराने वाली वस्तु बांधी गई है। हवा बहने पर बोतलों से आवाज निकलती है, जिसे सुनकर बंदर समेत अन्य पक्षी आम को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।

रोजगार भी दे रहे युवा किसान

सारसडोल गांव के कई लोग काम की तलाश में पहले गांव से पलायन कर जाते थे, लेकिन अब आम के बगीचे में उन्हें रोजगार मिल रहा है। रोजाना आम तोडऩे से लेकर कार्टून में पैकिंग करने के लिए संजय बघेल ने अपने ही गांव के 15 से 20 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इससे वहां कार्यरत कर्मचारी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण गांव में ही रहकर कर रहे हैं। संजय के पिता जमीन को ठेके पर पर दे देते थे, जिससे उन्हें साल भर में 50 से 60 हजार की आमदनी होती थी। वही विगत 5 वर्षों से संजय बघेल और उनके भाई ने स्वयं खेती करने का फैसला लिया। खुद आम की खेती करने की शुरुआत की। शुरुआती समय में उन्हें इसका उतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन पर धीरे-धीरे उन्हें लाभ होने लगा।

-156 प्रजाति की जड़ी बूटी-वनस्पति

सिवनी में 'संजीवनी' संरक्षण की दरकार

सिवनी। जंगलों को सुरक्षित रखने व समृद्ध बनाने का प्रयास लंबे समय से सिवनी जिले में किया जा रहा है। जिसके चलते सिवनी जिले में कई दुर्लभ औषधियां जड़ी बूटी और वनस्पति संरक्षित है। जो कई बीमारियों के उपचार में काम आती हैं। सिवनी जिले में कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जो जंगलों से घिरे हैं और प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है। जिले में प्राप्त औषधियों में कई गुण विद्वान रहते हैं। जो बड़े-बड़े असाध्य रोगों से लोगों को निजात दिलाते हैं। वहीं कई जगह वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जाता है जिसके नतीजा यह होता है कि औषधियों की संख्या घट जाती है। सिर के बाल झडऩे की समस्या दूर करने जंगल मिलने वाली दुर्लभ जटाशंकर औषधि की जड़ का उपयोग होता है। हृदय रोग जोड़ों के दर्द व अन्य बीमारियों में में उपयोग में आने वाली औषधि में गूगल का पेड़ उपयोग होता है।

औषधियों से जिला भरा

सिवनी जिले के जंगलों में कई लाभदायक पेड़,पौधे भी है जैसे गोरख इमली, पुनर्नवा की बेला, छोटी भटकटैया, शिवनाथ का पौधा, सफेद मूसली, काली मूसली, जंगली, हल्दी, चिरायता, शतावर, अमलतास, अर्जुन, निर्गुंडी, गोरखपुरकुंडी, शिवलिंगी, अकोल,कुल्लू गोंड, बायवरिंग, नागरमोथा, जंगली सूरन, काला धतूरा, भृंगराज, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, नीम सहित 156 प्रकार की कई औषधियों से जिला भरा हुआ है।

452 की बेल लता

सिवनी जिले के कुरई,केवलारी,धूमा, छपारा, बरघाट,घंसौर, धनोरा सहित कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गुणकारी औषधियां मिलती हैं। वही बेल लता की बात करें तो 452 प्रजातियां भी जिले में मिलती है। पेंच टाइगर रिजर्व बफर एरिया में 159 प्रजाति के पेड़,133 तरह की झाडिय़ां, 152 प्रकार की बेल,100 प्रकार की परजीवी बेलिया और घाट की 119 प्रजातियां शामिल हैं।

गुरबेल जीवन रक्षक

जिले में गुरबेल जैसी औषधि भी प्राप्त हो जाती है। जिसका उपयोग लोगों ने कोरोनाकाल में अधिकतर मात्रा में किया। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरी पौधे पर आश्रित रहता है। वही नीम के ऊपर चढ़ा हुआ गुरबेल काफी लाभदायक माना जाता है। जिसे कोरोना काल के समय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगों ने उपयोग किया। और उससे लाभ भी उन्हें मिला।

सभी प्रजातियों के पेड़ पौधों के अलावा दुर्लभ औषधियां पौधे भी जिले के जंगल में पाए जाते हैं। वनोपज के मामले में सिवनी पड़ोसी जिलों के से काफी आगे है। जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी तरह के प्रयास वन विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। औषधि पौधों का प्लांटेशन कराने के साथ समय-समय पर जैव विविधता की उपयोगिता समझाने अभियान भी चलाया जाता है।

एसएस उद्दे, सीसीएफ, वन विभाग, सिवनी

मानसून की मारः 30 फीसदी कम हुआ धान की खेती का रकबा

मॉनसून में देरी का असर खरीफ फसलों पर पड़ा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 23 जून 2023 तक देश में 129.53 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 6.12 लाख हे. कम है, 2021 के जून के तीसरे सप्ताह से तुलना करें तो चालू सीजन में 30 प्रतिशत क्षेत्र में बुआई कम हुई है।

मानसून में देरी के चलते खरीफ फसलों की बुआई पर असर देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र व पंजाब हैं। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान है और जून में होने वाली बारिश धान के लिए काफी महत्व रखती है, परंतु इस सीजन में धान उत्पादक राज्यों में बारिश न होने के कारण धान का रकबा कम हुआ है।

मंत्रालय की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की वेबसाइट बताती है कि चालू सीजन में जून के तीसरे सप्ताह तक 10.767 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि 2021 में इस समय तक 36.02 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। यहां तक कि पिछले साल 2022 में भी मॉनसून में देरी होने के बावजूद 16.456 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी थी।

पंजाब के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। यहां 23 जून 2023 तक केवल 68 हजार हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है, जबकि 2022 में 3.57 लाख हेक्टेयर और 2021 में 15.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हो चुकी थी।

खरीफ की बुआई में हो रही देरी को लेकर डाउन टू अर्थ ने कुछ प्रमुख राज्यों के किसानों से बात कर जानने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी बारिश न होने के कारण जून में वे ढ़ंग से बुआई नहीं कर पाए थे, लेकिन चालू सीजन और भी बुरा साबित होने वाला है।

मध्य प्रदेश में किसान मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में मॉनसून 15 जून तक आ जाता है, लेकिन 23 जून तक मॉनसून नहीं पहुंचा है। आने वाले दो—तीन दिनों में भी इसके आने की कोई पुख्ता सूचना नहीं है, इससे खरीफ फसलों में देरी होने की आशंका है। खासकर सोयाबीन बोने वाले किसान मौसम की लेटलतीफी से ज्यादा परेशान हैं। धान की फसलों में रोपा (नर्सरी) लगाने की तैयारी चल रही है। किसानों ने खाद—बीज की पूरी तैयारी कर ली है। नर्मदापुरम् जिले के किसानों का कहना है कि तूफान के कारण मॉनसून पिछड़ गया है, इससे हमारी बोवनी (बुआई) भी प्रभावित हो रही है। यदि ठीक वक्त पर मॉनसून आ गया होता तो उनकी आधी से अधिक बोवनी हो गई होती।

वहीं महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले साल राई और पीला मोजॅक रोग के कारण उनकी फसल को भारी नुकसान हुआ था। एक एकड़ में केवल दो से ढाई क्विंटल ही उत्पादन हुआ था। इस साल बारिश न होने के कारण अब तक बुआई नहीं कर पाए हैं। बुआई में देरी के कारण इस बार भी सोयाबीन को भारी नुकसान होने का डर है।

दूसरी तरफ मॉनसून में देरी से उत्तर प्रदेश के किसानों का नुकसान बढ़ गया है। एक तो देर से धान की नर्सरी डालने से धान की फसल लेट होगी, दूसरे जो नर्सरी पहले डाली उसमें सिंचाई का खर्च अधिक आया है और खेतों में पानी अधिक गर्म हो जाने से कई किसानों की नर्सरी गल गई। जिन्हें दोबारा बोना पड़ रहा है।

वहीं, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि मॉनसून में देरी को देखते हुए किसानों को धान की नर्सरी पर समय खराब नहीं करना चाहिए। लखनऊ में कृषि वैाानिकों के अनुसार किसानों को अब नर्सरी डालने से अच्छा है कि धान की सीधी बुआई कर दें। इससे कम से कम दस दिन का समय बच जाएगा। ये बारिश काम की है जिन्हें उड़द, मक्का आदि की बुआई करनी है वो कर सकते हैं।

बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से अधिकांश जगह धान के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अधिकांश किसानों का कहना है कि वैसे जून के पहले सप्ताह में हम लोग रोपनी शुरू कर देते थे। अब 5 से 6 दिन और बारिश की स्थिति को देख लेते हैं, उसके बाद मशीन से पटवन शुरू करके रोपाई शुरू करेंगे। नहर में पानी बहुत सूख चुका है। पिछले साल भी सूखाड़ की वजह से हम लोगों का काफी नुकसान हुआ था।

मॉनसून में देरी और अत्यधिक गर्मी की स्थिति के कारण ओडिशा में खरीफ के लिए कृषि गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। किसानों ने कहा कि परिणामस्वरूप कृषि गतिविधियों में 15 दिनों की देरी हुई है। खरीफ के दौरान ओडिशा में धान, मूंगफली, मक्का, दालें, बाजरा, कपास, अदरक और हल्दी जैसी फसलें उगाई जाती हैं।

ओडिशा का सकल फसल क्षेत्र 83 लाख हेक्टेयर से अधिक है। राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले खरीफ के दौरान शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.30 लाख हेक्टेयर था। चूंकि इस साल पानी की कमी के कारण बुआई शुरू नहीं हुई है, इसलिए विभाग ने अभी तक इस साल शुद्ध बुआई क्षेत्र का अनुमान नहीं लगाया है।

जून के पहले सप्ताह से राज्य में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकांश निगरानी केंद्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। संबलपुर और सोनपुर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कई अन्य केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

भीषण गर्मी के कारण अधिकांश जलस्त्रोत सूख गये हैं। मॉनसून में देरी के कारण बांधों के जलाशयों में जल स्तर भी कम हो रहा है। जलधाराओं में पानी नहीं होने से लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है।

हीराकुंड बांध के अधिकारियों को 15 जून तक बांध कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी छोड़ना होता है, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे, क्योंकि जलाशय में जल स्तर तेजी से घट रहा है। हीराकुंड बांध कमांड क्षेत्र में ज्यादातर बरगढ़ में सिंचित भूमि शामिल है, जिसे ओडिशा का धान का कटोरा कहा जाता है। इसमें संबलपुर और सुबर्नापुर के कुछ हिस्से भी शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में मॉनसून सामान्य समय से लगभग एक सप्ताह की देरी से दक्षिण बंगाल के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा है। इस वजह से बीज आधार की बुआई और तैयारी, जिसे स्थानीय भाषा में बिजटोला कहा जाता है, काफी प्रभावित हुई है।आमतौर पर राज्य में बुआई की तैयारी मॉनसून की शुरुआत के साथ जून के मध्य से शुरू होती है और लगभग 25 दिनों तक चलती है।

भारतीय और विदेशी गोवंश की उन्नत नश्लें और उनका महत्व

» डॉ. सोनू कुमार यादव
» डॉ.अंजनी कुमार मिश्रा
» डॉ. राहुल चैरसिया
» डॉ. उपेन्द्र सिंह नरवरिया
» डॉ. भावना अहरवाल

पीएचडी शोध छात्र, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पीएचडी शोध छात्र, सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक

» डॉ. प्रमोद शर्मा, सहायक प्राध्यापक
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, मप्र.

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मह्, मप्र.

भारत में प्राचीन काल से ही पशुपालन व्यवसाय के रुप मे प्रचलित रहा है। भारत में 70फीसदी आबादी ग्रामीण है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 53578 मिलियन है, जो 2012 की तुलना मे 4.6 प्रतिशत अधिक है।

पशुधन गणना के अनुसार मादा मवेशी (गायो कीं कुल संख्या) 145.12 मिलियन आंकी गई, जो पिछली गणना से 18 प्रतिशत अधिक है। पशुओं के समूह को जो कि विभिन्न गुणों में एक जैसे देखने मे, शारीरिक अनुपात में, आकृति मे एक तरह के हो, और एक ही वंश के हो, नस्ल कहलाते हैं।

भारतीय गायों की नस्लें: भारत में गायों की नस्लों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है-

दूध देने वाली नस्लें: 1. साहीवाल, **2.** लाल सिन्धी, **3.** गिरि, **4.** देओनी।

दूध एवं खेती दोनों के काम आने वाली नस्लें: 1. हरियाणा, **2.** थारपारकार, **3.** कांकरेज, **4.** अंगोल।

खेती में काम आने वाली नस्लें: 1. अमृत-महल, **2.** कंगायम, **3.** मालवी, **4.** हल्लीकर, **5.** सीरी।

दूध देने वाली नस्लें: 1.साहीवाल,अन्य नाम-लोला, मोन्टगुमरी, यह नस्ल पाकिस्तान के मोन्ट-गुमरी जिले में तथा भारत के पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जिलों में पायी जाती है।

उत्पादन: यह नस्लऔसतन 2200-2500 किग्रा दूध 300 दिन में देती है। नर पशु छोटे मोटे खेती के कामों के लिए उपयोगी।

लाल सिन्धी: इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान के करांची तथा हैदराबाद है। भारत के उत्तरी राज्यों में भी पाई जाती है।

उत्पादन: इस नस्ल का औसत दुग्ध उत्पादन 2000 किग्रा. प्रति ब्यात होता है। नरपशु खेती या दूसरे भार उठाने के लिए उपयोगी।

गिरः अन्य नाम-काठियाबाड़ी, सूरती, देसान, इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात राज्य का गिर जंगल हैं। यह काठियाबाड़ के जूनागढ़ तथा पश्चिमी भारत में पायी जाती हैं।

उत्पादन: इस नस्ल की औसत दुग्ध क्षमता 1700 किग्रा. प्रतिब्यात होती हैं। सांड खेती के कामों के लिए उपयोगी होते हैं।

देओनी: अच्छी दुधारू नस्ल है।

उत्पादन: औसत दूध उत्पादन क्षमता 1500 किलोग्राम प्रति ब्यात हैं। अगर अच्छी तरह पाला जाये तो यह 3000 किलोग्राम प्रतिब्यात दूध दे सकती हैं। बैल खेती के कामों के लिए उपयोगी।

दूध एवं खेती दोनों के काम आने वाली नश्लें: हरियाणा- इस जाति का मूल स्थान रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा दिल्ली है। इसके अतिरिक्त यह जाति जींद, नाभा, पटियाला, अमरपुर, भरतपुर, जयपुर तथा उत्तरप्रदेश के पश्चिम में भी पायी जाती हैं।

उत्पादन: यह एक दुई उद्देषी नस्ल है। इस जाति की मध्यम दर्जे की गायें एक ब्यात में लगभग 1500 किलोग्राम दुध देती हैं। इस जाति के बैल अपने गुणो और शक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।

अंगोल-अन्य नाम: नैल्लोर: इस जाति के पशु आंध्र प्रदेश के अंगोल नामक इलाके के नेल्लोर और गुंटूर जिले में पाए जाते हैं।

उत्पादन: औसतन एक ब्यात में 800 से 1000 किग्र तक दूध देती है बैल कृषि के काम आते हैं।

थारपारकर-अन्य नाम: थारी: इसका मूल स्थान पाकिस्तान का थार पारकर जिला है। राजस्थान जोधपुर जैसलमेर जिलों में भी पाई जाति हैं।

उत्पादन: यह एक प्रमुख दुई उद्देषी पशु है। एक ब्यात में 2 हजार किग्रा दूध देती है। इस जाति के साडों को दुधारू नस्ल सुधार कार्य के लिए अच्छा समझा जाता हैं।

कांकरेज: अन्य नाम-बिन्नआई, बगाड़िया, वधियार। इस जाति के पशु बड़ौदा, सूरत जिले एवं कच्छ क्षेत्र में पायी जाती हैं।

उत्पादन: इस नस्ल की गाय एक ब्यात में औसतन 1500-1800 किलोग्राम दूध देती हैं। बैल खेती के कार्य के लिए उपयोगी होते हैं।

खेती में काम आने वाली नस्लें: अमृतमहल: इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान कर्नाटक राज्य है। मद्रास एवं मुंबई के दक्षिणी भागों में भी पायी जाती हैं।

उत्पादन: गाय कम दूध देती है। बैल खेती तथा तांगे-गाड़ियों में जोतने और तेज चाल, कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम है।

कंगायम: अन्य नाम-कंगाबंद कांगू: इस नस्ल के पशु कोयम्बतूर जिले में पायी जाती हैं।

उत्पादन: कम दूध वाली। भारवाही कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं।

मालवी: इस नस्ल का मूल स्थान मप्र का मालवा है। यह नस्ल राजस्थान में भी पायी जाती हैं। यह खेती की नस्ल हैं।

सीरी: यह दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान में पायी जाती हैं।

हल्लीकर: कर्नाटक राज्य की हासन और तुमकुर की नस्ल हैं।

गाय की विदेशी नस्लें: विदेशों के दुधारू पशुओं की नस्ल भारतीय नस्लों से ज्यादा दूध देती हैं। विदेशी गायों का मुख्यत: जर्सी, होलेस्टीन फ्रिजियन, रेडडेन और ब्राउन स्विस नस्लों का प्रयोग भारत में हो रहा है।

जर्सी: इस नस्ल की उत्पत्ति इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप से हुई है। औसत दूध उत्पादन की क्षमता 3500-4000 लीटर प्रतिब्यात है। दूध में फैट 4.5 से 5.5 प्रतिशत तक होता हैं।

होलस्टीन-फ्रीजियन: यह नीदरलैंड की नस्ल हैं। पशुओ का रंग काला और सफेद होता हैं। यह नस्ल संसार की सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली मानी जाती है। औसतन दुग्ध उत्पादन प्रतिब्यात 6000-7000 लीटर होता है। इसके दूध में फैट कम अर्थात 3.0 से 3.5 प्रतिशत होता है।

रेड-डेन: यह डेनमार्क की नस्ल है। पशुओं का रंग गहरा लाल होता है। नर पशु काला पन लिए हुए होता है। प्रतिब्यात दुग्ध उत्पादन 4900 लीटर होता है। दूध में फैट की मात्रा 4.0-4.5 प्रतिशत होता है।

ब्राउनस्विस: यह स्वीटजरलैंड की नस्ल है। इस का रंग गहरा बदामी होता है। प्रतिब्यात औसतन एक गाय 5000 से 6000 लीटर दूध देती है।

बढ़ता तापमान और प्रदूषणः गुस्सैल होंगे कुत्ते, मानव व्यवहार में भी आएगा बदलाव

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं का दावा है कि बढ़ते तापमान, गर्मी, अल्ट्रावायोलेट और ओजोन प्रदूषण के साथ डॉग बाइट की यह घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। शोधकर्ता तनुजीत डे के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने डॉग बाईट की 69,525 घटनाओं का अध्ययन किया है। यह सभी घटनाएं 2009 से 2018 के बीच अमेरिका के आठ शहरों में दर्ज की गई थी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने उनके मिजाज पर बढ़ते तापमान और प्रदूषण के प्रभावों का भी आंकलन किया है। इस रिसर्च में जो नतीजे सामने आए हैं, वो परेशान कर देने वाले हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ओजोन, यूवी विकिरण और तापमान में वृद्धि के साथ डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। रिसर्च में पीएम 2.5 और इन घटनाओं के बीच कोई सम्बन्ध नहीं देखा गया। इसी तरह बरसात के दिनों और छुट्टियों में कुत्तों के हमले की घटनाओं में कमी देखी गई थी। शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गर्म और धूल-धुंए से भरे दिन में कुत्ते इंसानों पर ज्यादा हमला करेंगें। खासकर जब प्रदूषण ज्यादा हो तो उनके हमले की सम्भावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह बढ़ता तापमान भी कुत्तों को कहीं ज्यादा आक्रामक बना रहा है। रिसर्च के मुताबिक वातावरण में जब यूवी विकिरण ज्यादा था तो कुत्तों के काटने की घटनाओं में 11 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। अत्यधिक गर्म दिनों में यह घटनाएं चार फीसदी और ओजोन के बढ़ते स्तर के चलते इन घटनाओं में तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी।

सिर्फ कुत्ते ही नहीं इंसानों और अन्य जीवों के व्यवहार में भी आ रहा है बदलावः रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में कुत्ते और हिंसक होते जाएंगे। देखा जाए तो कुत्तों के व्यवहार में आता यह बदलाव इंसानों के समान ही है। पहले किए अध्ययनों में भी यह साबित हो चुका है कि तापमान और वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर मनुष्य अधिक हिंसक अपराध करते हैं। इतना ही नहीं बढ़ते तापमान के साथ यह प्रवत्ति बंदर, चूहों जैसे जीवों में भी देखी गई है। जर्नल एनवायर्नमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक बढ़ता तापमान हिंसक घटनाओं में वृद्धि की वजह बन सकता है। कई अन्य अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बढ़ते तापमान की वजह से अपराध ज्यादा होते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, उन सभी कारकों को समझना जरूरी है जो जानवरों की आक्रामकता में योगदान करते हैं।

पंजौर गिद्ध संवर्धन केंद्र से 20 गिद्ध वन विहार लाए गए

भोपाल। जागत गांव हमार

हरियाणा स्थित पिंजौर गिद्ध संवर्धन केन्द्र से 20 व्हाइट रम वल्चर (सफेद पीठ वाले गिद्ध) वन विहार उद्यान भोपाल में शनिवार को लाये गये। इसके बाद इन्हें केरवा के क्वारंटाइन सेंटर पहुँचाया गया। यह सभी गिद्ध पूर्णत: स्वस्थ हैं। वन विहार संचालक पदमाप्रिया बालाकृष्णन ने बताया कि लाए गए गिद्धों में 5 मादा और 10 सब एडल्ट गिद्ध हैं। इनको विशेष रूप से तैयार किए गए क्रेट्स में रखकर सड़क मार्ग से 1100 किलोमीटर दूरी तय कर लाया गया। वल्चर विशेषज्ञ रोहन एवं वेटनरी डॉ. रजत कुलकर्णी इस यात्रा के दल में शामिल थे। पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) शुभरंजन सेन की उपस्थिति में गिद्ध वन विहार पहुँचे। इन गिद्धों को 45 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद केरवा स्थित गिद्ध संरक्षण-संवर्धन केन्द्र की एवरी में छोड़ा जाएगा।

पशुपालक हरे चारे के लिए नेपियर हाइब्रिड बाजरा रोपें

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के डॉ. बीएस किरार, डा आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके जाटव द्वारा पशुपालकों को समसामयिकी सलाह अंतर्गत बताया जाता है कि पशुओं के लिए सालभर हरा चारा प्राप्त करने के लिए नेपियर हाइब्रिड बाजरा लगाएं। जिले में इस हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ पशुपालकों को हरे चारे के प्रदर्शन अंतर्गत नेपियर हाइब्रिड बाजरा की कटिंग, रूट स्लिप, नि:शुल्क प्रदान करेगा। जिन्हें वर्षात प्रारंभ होने पर दोमट भूमि पर लगा देना चाहिए। उस खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा फसल सड़ जाएगी या फिर उसकी अच्छी बढ़वार बड़ नहीं होगी। नेपियर हाइब्रिड बाजरा बहुवर्षीय घास है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई सुविधा है तब वह किसान इसकी साल में 10.12 बार कटाई कर सकते हैं। इस घास को लगाने का उपयुक्त मौसम खरीफ में रहता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुपालकों के पास साल भर हरे चारे की उपलब्धता न रहने से दुधारू पशुओं के लिए बाजार से पशुआहार खरीदना पड़ता है, जिससे पशुओं पर खर्च बढ़ जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र जिले में अधिक से अधिक पशुपालकों तक बहुवर्षीय हरा चारा फैलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनेपियर हाइब्रिड बाजरा घास फसल के नि:शुल्क प्रदर्शन के लिए किसानों को नि:शुल्क कटिंग प्रदाय कर रहे हैं। जो भी पशुपालक नेपियर हाइब्रिड बाजरा लगाना चाहते हैं, वह कृषि विज्ञान केंद्र, कुंडेश्वर रोड, टीकमगढ़ में सम्पर्क कर नेपियर हाइब्रिड बाजरा की कटिंग ले जा सकते हैं।

सही समय पर सोयाबीन की बुआई किसानों को करगी मालामाल

सही समय पर सोयाबीन की बोवनी किसानों को कर दगी मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ सीजन में सोयाबीन तिलहन की मुख्य फसल है। कई राज्यों में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। सोयाबीन उत्पादक कई राज्यों में अभी मानसून के आने में देरी है जिससे इन राज्यों अभी काफी तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में किसानों को सोयाबीन की बोवनी कब और कैसे करनी चाहिए।

वैसे तो अभी तक किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि सोयाबीन की बोवनी के लिए जून माह के दूसरे सप्ताह से जुलाई माह का प्रथम सप्ताह सबसे उचित होता है, परंतु यदि मानसून के आने में देरी हो तो किसान इसकी बोवनी थोड़ा रुककर कर सकते हैं। किसानों को मानसून आने के बाद ही जब कम से कम 10 सेमी वर्षा हो जाए उसके बाद ही सोयाबीन की बोवनी करनी चाहिए।

बोवनी के समय उर्बरक का प्रयोग

किसानों को अंतिम बखरनी के पहले पूर्णत: पकी हुई गोबर की खाद की अनुशंसित मात्रा 5 से 10 टन/हेक्टेयर या कम्पोस्ट 5 टन/हेक्टेयर या वर्मी कम्पोस्ट 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए।

सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों 25:40:60:20 किलोग्राम/हेक्टेयर (नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर) की पूर्ति केवल बोवनी के समय करनी चाहिए। इसके लिए इनमें से किसी भी एक उर्वरक का चयन किया जा सकता है। यूरिया 56 किग्रा + 375-400 किग्रा सिंगल सुपर फास्फेट व 67 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश, या डीएपी 125 किग्रा + 67किग्रा म्यूरेट आफ पोटाश + 25 किग्रा /हेक्टेयर बेन्टोनेट सल्फर, या मिश्रित उर्वरक का 200 किलोग्राम + 25 किग्रा/ हेक्टेयर बेन्टोनेट सल्फर का छिड़काव करें।

किसान इस तरह करें सोयाबीन की बोवनी

पिछले कुछ वर्षों में मानसूनी बारिश की अनिश्चितताओं के चलते सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान होता रहा है। जिसके चलते बहुत से किसानों ने तो सोयाबीन की खेती करना ही छोड़ दिया है। सोयाबीन को अधिक वर्षा या कम वर्षा की स्थिति से बचाने के लिए किसान ऊंची क्यारी विधि या रिज एंड फरो विधि से ही सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए। किसानों को उपलब्धता अनुसार अपने खेत में विपरीत दिशाओं में 10 मीटर के अंतराल पर सब सोइलेर नमक यंत्र को चलाना चाहिए, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी एवं सूखे की अनपेक्षित स्थिति में फसल को अधिक दिन तक बचाने में सहायता मिलेगी।

लघु धान्य फसलों की उत्पादन तकनीक का दिया प्रशिक्षण

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके जाटव, एवं डॉ. आईडी सिंह द्वारा गांव खुशीपुरा विख बल्देवगढ़ में कृषक एवं महिलाओं को लघु धान्य फसलों की उत्पादन तकनीक पर मंजरी फाउंडेशन गैर सरकारी संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण में कोदो, रागी, सांवा, बाजरा, ज्वार की उत्पादन तकनीक अन्तर्गत महत्वपूर्ण तकनीकी बिन्दुओं, उन्नत किस्म, बीज दर, बीजोपचार करने की विधि, सन्तुलित उर्वरक का प्रयोग, समय पर निदाई-गुड़ाई और कतार से बुवाई का काम आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लघु धान्य फसलों में कम उर्वरक और कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इनमें कीट व्याधियों की समस्या भी बहुत कम आती है। इनकी खेती हल्की एवं मध्यम भूमि पर उचित जल निकास वाली भूमियो पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। लघु धान्य फसले औषधीय के क्षेत्र में भी काफी लाभकारी हैं। इसलिए इन्हें अपने भोजन में अवश्य रूप से शामिल करें, जिससे वर्तमान में मनुष्य के शरीर में बढ़ती बीमारियों मधुमेह, ब्लड प्रेशर, पेट की बीमारियों, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों से काफी हद तक शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। लघु धान्य फसलों की खेती प्राकृतिक खेती के रूप में करना ज्यादा आसान और लाभकारी है। हमारे पूर्वज ज्वार, बाजरा, मक्का, कोंदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना एवं कंगनी की खेती करते भी थे और इन्हे अपने भोजन में शामिल करके स्वस्थ एवं तन्दरूस्त रहते थे। हमे अपनी भूमि, जल, वायु एवं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे-धीरे बढ़ना ही होगा।

किसानों की किस्मत चमका सकती है चन्दन की खेतीः सरिता अभय शंकर दुबे

डा. शशिकांत सिंह,
लखनऊ। जागत गांव हमार

वर्तमान में किसानों का रुझान नगदी फसलों की खेती की तरफ ज्यादा है। किसान कम लागत और कम परिश्रम में ज्यादा फायदा देने वाली फसलों की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में चन्दन की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। चंदन के औषधीय गुण के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत मांग है। चन्दन की खेती कम परिश्रम एवं अत्यधिक लाभ देने में सक्षम है।

कई काम आती है चंदन की लकड़ीः चंदन के पेड़ से निकलने वाला तेल और लकड़ी दोनों औषधियां बनाने के काम आती हैं। साबुन, कॉस्मेटिक्स और पर्फ्यूम में चंदन के तेल को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस खेती को शुरू करने के लिए आपको एक लाख लगाने होंगे, जिससे कम से कम साठ लाख तक का मुनाफा हो सकता है।

उत्पादन 100 टन और मांग लगभग 8000 टनः भारत में चन्दन का कुल उत्पादन 100 टन के आसपास है, किन्तु इसकी खपत प्रति वर्ष 7,000 से 8,000 टन तक रहती है, जिस वजह से इसकी कीमत काफी महंगी होती है। कई राज्यों में चन्दन की खेती पर प्रतिबंध है। कई राज्य इसकी खेती पर सब्सिडी भी देते हैं, खेती के लिए कानूनी मान्यता की भी जरूरत होती है।

तैयार होने में लगता है 10 से 15 वर्ष का समयः इसके पौधों को तैयार होने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है, जिसके पौधों की लम्बाई 20 से 25 मीटर तक होती है। चन्दन पेड़ के सभी भागों को इस्तेमाल में लाया जाता है।

खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जलवायु और तापमान

चन्दन की खेती के लिए लाल, बलुई, चिकनी, दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है। चन्दन के खेत में जल जमाव किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए तथा भूमि का पी एच मान 7 से 9 के मध्य होना चाहिए। चन्दन की खेती जलोढ़ और नम मिट्टी में करने से तेल की मात्रा कम प्राप्त होती है। चन्दन का पौधा शुष्क जलवायु वाला होता है, इसके पौधों को अधिक ठंडी जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। जाड़े में गिरने वाला पाला इसके पौधों के लिए उचित नहीं होता है। इसके पौधे अधिक धूप को आसानी से सहन कर सकते है। इसके पौधों को अधिकतम 500 से 625 मिमी बारिश की आवश्यकता होती है। चन्दन के पौधों को अधिकतम 45 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है।

चन्दन की किस्में

चन्दन मूलतया दो प्रकार का होता है। लाल चन्दन और सफेद चन्दन। लाल चंदन की खेती दक्षिण भारत के राज्यों में होती हैं, जबकि सफेद चंदन उत्तर भारत के राज्यों में हो सकता है।

लगाने का सही समयः चन्दन के पौधों की रोपाई का सही समय बारिश का मौसम होता है। चन्दन को बीज और पौध दोनों ही रूप में लगाया जाता है।

चन्दन के खेत की तैयारी और उर्वरक

इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद खरपतवार,अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इससे बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा करना चाहिए। पलेवा के बाद रोटावेटर से खेत की दो से तीन जुताई करके पौधों की रोपाई के लिए गड्ढों को तैयार कर लिया जाता है। यह गड्ढे 10 फीट की दूरी पर 2 फ़ीट गहरे और 2 फ़ीट चौड़े होने चाहिए। इन गड्ढों में मिट्टी के साथ गोबर की खाद को अच्छे से मिलाकर भर देना चाहिए। इसकी खेती में इस तरह के सहायक पौधों को जरूर लगाना चाहिए।

चन्दन के पौधों की सिंचाई, कटाई, पैदावार और अनुमानित लाभ

चन्दन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में पौधों में नमी बनाये रखने के लिए दो से तीन दिन में पानी देना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सप्ताह में एक बार पौधों की सिंचाई अवश्य करे।

जितना पुराना पौधा, उतना अधिक लाभः चंदन का पौधा जितना पुराना होता है, उतना ही मूल्यवान होता है। इसके पेड़ की कटाई न करके उसे जड़ से उखाड़ लिया जाता है। चन्दन की कटाई से पहले सरकार से परमिशन लेना होता है। चन्दन के एक विकसित पेड़ से 25 से 40 किलो लकड़ी प्राप्त हो जाती है तथा एक एकड़ के खेत में 400 पौधों को तैयार किया जा सकता है। चंदन की लड़की का वर्तमान बाजारी भाव 6 से 12 हजार रूपए प्रति किलो है। जिससे किसान 25 किलो के एक पेड़ से 10 से 15 वर्षों में 1 से 2 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, तथा एक एकड़ में तैयार 400 पेड़ों से किसान 5 से 8 करोड़ तक की कमाई करके आसानी से करोड़पति बन सकते हैं।

अगर रखरखाव समय समय पर खाद पानी का ध्यान रखा जाय तो चंदन की खेती किसानों के लिए एफडी का काम करेगी। उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं धरती पुत्र भारत के फाउंडर सरिता अभय शंकर दूबे बताते हैं कि मेरे एक गुजराती मित्र ए सी चौहान जो बड़ोदरा गुजरात से हैं। सोलह वर्ष पहले चंदन का रोपण किया था। उनका चन्दन पिछले वर्ष करीब सात करोड़ में बिका है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बहुत से साथियों ने इसका पौधरोपण किया है। कुछ साथी भविष्य में लाभ के लिए अपने खाली पड़े प्लाट या खेतों के कुछ हिस्सों में इसका रोपण कर रहे हैं।

सहायक फसलेंः चन्दन के पौधों को तैयार होने में 10 से 15 वर्ष का समय लग जाता है। इस दौरान चन्दन के पौधों के मध्य दलहन या बागबानी फसल उगाकर अतिरिक्त कमाई की जा सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

केला की सघन बागवानी करके अधिक उपज लें किसानः प्रो एसके सिंह

बालाघाट। जागत गांव हमार

यह केला उत्पादन की एक नयी विधि है। इसमें उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रति इकाई क्षेत्रफल केला के पौधों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस विधि में उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन खेती की लागत घटती है।

उर्वरक एवं पानी का समुचित एवं सर्वोत्तम उपयोग हो जाता हैं। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं देश के अन्य हिस्सों में किये गये प्रयोगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रोबस्टा एवं बसराई प्रजाति के पौधों की संख्या/हेक्टेयर बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।केला खेती की इस विधि का प्रयोग कई वर्षों से केला की खेती कर रहे करे तो ज्यादा बेहतर होगा।

पहली बार केला की खेती करने जा रहे केला उत्पादक किसानों को सलाह दी जा रही है की इस विधि का प्रयोग न करें क्योंकि इसमें कुशल दक्षता की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,कोयंबटूर में हुए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकन्दों की संख्या एक स्थान पर एक न रखकर तीन रखकर तथा पौधों से पौधों तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 ×3 मीटर रख कर प्रति हेक्टेयर 5000 तक पौधा रखा जा सकता है। इसमें नेत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 25 प्रतिशत मात्र परम्परागत रोपण की तुलना में बढ़ाना पड़ता है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

आजकल सघन रोपण विधि के अन्तर्गत कावेन्डीश समूह के केलों (ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार पौधें) को जोड़ा पंक्ति पद्धति में लगाने की संस्तुति की जाती है। इस विधि में सिचाई टपक विधि द्वारा करने से सलाह दी जाती है। इसके कई फायदे है। केला की प्रथम फसल मात्रा 12 महीने में ली जा सकती है तथा उपज कम से कम 60 टन से ज्यादा मिल जाती है।

प्रदर्शनी में कृषि मंत्रियों, जी20 देशों के विभिन्न प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक लोगों की रही भागीदारी

भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया

नई दिल्ली।

जी 20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक 15 से 17 जून तक हैदराबाद में आयोजित की गई थी। इस आयोजन के दौरान, पीएम मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को मिलेट्स पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया और श्री अन्न को बढ़ावा देने और अपनाने में प्रमुख संस्थान की भूमिका को दोहराया।

तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान आईसीएआर-आईआईएमआर के तकनीकी भ्रमण की भी व्यवस्था की गई। भ्रमण और प्रदर्शनी में कृषि मंत्रियों, जी20 देशों के विभिन्न प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित 300 से अधिक लोगों की भारी भागीदारी देखी गई।

कृषि मंत्रियों ने आईआईएमआर परिसर में स्थापित विभिन्न मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों का भी दौरा किया, जिसमें प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, बेकरी इकाई और पैकेजिंग इकाई, इसके बाद फ्लेकिंग इकाई, कोल्ड एक्सर्ट्ज़न लाइन आदि शामिल हैं। ये प्रसंस्करण मशीनरी विभिन्न मिलेट्स मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे बाजरा मफिन, कृकीज़ और नूडल्स बनाने के लिए सुसज्जित हैं। मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने भी न्यूट्रीहब का दौरा किया। न्यूट्रीहब भारत सरकार समर्थित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर है जिसकी मेजबानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद द्वारा की जाती है। न्यूट्रीहब-आईआईएमआर में इनक्यूबेशन प्रोग्राम को आवश्यक तकनीक और सहायता प्रदान करके मिलेट्स स्टार्ट-अप को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस भ्रमण का मुख्य आकर्षण मिलेट्स प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी में देश भर के चयनित एफ्मीओ, मिलेट्स निर्यातकों और मिलेट्स आधारित स्टार्टअप्स द्वारा 30 अद्वितीय स्टालों को प्रदर्शित किया गया।

हरदा से भाजपा विधायक और मंत्री कमल पटेल का रिपोर्ट कार्ड

कृषि आधारित उद्योगों का इंतजार

हरदा।

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले विधानसभा क्षेत्र हरदा-खिरकिया से कमल पटेल अपनी विधायकी के 25 वर्ष पूरे करने वाले हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं लेकिन उनके क्षेत्र में किसानों को कृषक सुविधाओं और संसाधओं का इंतजार है। कृषकों के तकनीकी प्रशिक्षण तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं खाद एवं बीज की गुणवत्ता को लेकर नियंत्रण के कोई प्रभावी कदम नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि उपज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के लिए उद्योग इकाई एवं कोल्ड स्टोरेज की कमी भी खलती है। इलाके में हंडिया क्षेत्र के नहर के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। खिरकिया विकासखंड में लंबे समय से शासकीय महाविद्यालय की मांग की जा रही है वहीं हरदा जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय की मांग भी अब तक अधूरी है।

अब तक नहीं मिलीं यह सुविधाएं- हरदा शहर, खिरकिया शहर एवं खंडवा-नर्मदापुरम स्टेट हाईवे पर भिरंगी में रेलवे के ओवरब्रिज अब तक नहीं बन पाया है। विधायक कमल पटेल का जनता से किया कृषि महाविद्यालय खोलने का वादा भी पूरा नहीं हो सका है।

2013 में दिखी थी नाराजी

मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार विधायक एवं मंत्री कमल पटेल राजनीति में वर्ष 1989 से सक्रिय हैं। वे क्षेत्र के विधायक पहली बार वर्ष 1993 में चुने गए। इसके बाद लगातार वर्ष 1998, 2003, 2008 में विधायक बने। लेकिन वे वर्ष 2013 में कांग्रेस के डा. आरके दोगने से हार गए। इसका प्रमुख कारण पुराना कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहना था। माना गया कि वे क्षेत्र की जनता को सौगात दिलाने में सफल नहीं हुए जिसका असंतोष था।

योजना का देश में हुआ नाम

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जिले से शुरू कराने का श्रेय भी स्थानीय विधायक को जाता है। ड्रोन से आबादी की भूमि का सर्वे कर भू अधिकार देने की इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का दूसरा सेंटर आफ एक्सीलेंस शुरू करने की योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत भी पटेल की प्रमुख हरदा को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए कई विकास कार्य किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जिसकी शुरुआत हरदा जिले से हुई। जल्द हरदा जिला शत प्रतिशत सिंचाई वाला प्रदेश का पहला जिला बनने वाला है। सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। जो कहा सो किया।

कमल पटेल, विधायक एवं कृषि मंत्री

कृषि मंत्री कमल पटेल सिर्फ विकास की बात करते हैं। वे न तो कृषि कॉलेज खुलवा पाए, न खिरकिया शासकीय कॉलेज खुलवा पाए, न ही हरदा के शासकीय आदर्श महाविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का भवन बनवा पाए। इसके अलावा वे हरदा, खिरकिया और भिरंगी में रेलवे ओवरब्रिज अब तक नहीं बनवा सके।

डॉ. आरके दोगने, पूर्व विधायक, हरदा

श्री अन्न एवं आर्गेनिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करें

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को श्रीअन्न एवं आर्गेनिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण कर्ज में बढ़ोतरी लिए नाबार्ड से कदम उठाने को कहा ताकि कृषि के साथ गैर कृषि सेक्टर में भी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कृषि और गैर कृषि दोनों ही सेक्टर में उत्पादकता बढ़ने से ही ग्रामीण इलाके का विकास होगा। वित्त मंत्री ने नाबाडज़ के चेयरमैन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्त सेवाओं विभाग के सचिव भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने नाबाडज़ से कहा कि उन्हें किसान उत्पादक संघ (एफ्मीओ) के साथ मिलकर खास कर उत्तर पूवज़ राज्यों में आगेज़निक उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए श्रीअन्न का उत्पादन व इसकी मार्केटिंग राष्ट्रीय महत्व का विषय है। नाबार्ड को किसानों के साथ मिलकर श्रीअन्न के उत्पादन एरिया को बढ़ाने के साथ पहले से श्रीअन्न का उत्पादन कर रहे किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

किसानों को करना चाहिए प्रोत्साहित

वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड को दाल, श्रीअन्न, तिलहन जैसे उत्पादों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें पानी की खपत कम है, लेकिन मुनाफा अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण बैंकों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने की जरूरत है तभी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम को सार्थक बनाया जा सकता है। उन्होंने नाबार्ड से कर्ज देने के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करने का निर्देश दिया ताकि देश के सभी हिस्सों में ग्रामीण इलाके का विकास हो सके।

पौष्टिक सुपरफूड एवोकाडो की पहली शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंची

नई दिल्ली।

आईजी इंटरनेशनल, एक ताजा फल आयातक ने मुंबई के बंदरगाह पर ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो के पहले शिपमेंट को सफलतापूर्वक आयात किया है। इसमें प्रीमियम एवोकाडो के 176 कार्टन आयें हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं के अनुभव को बढ़ाएंगे।

इस उपलब्धि के बारे में आईजी इंटरनेशनल में निदेशक, सोर्सिंग और मार्केटिंग सुश्री शुभा रावल ने कहा, हम ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो के पहले शिपमेंट को सफलतापूर्वक आयात करने के लिए रोमांचित हैं। हमारा मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो की शुरूआत भारतीय उपभोक्ताओं के अनुभव को काफी बढ़ाएगी और भारत में ताजा उत्पाद उद्योग के विकास में योगदान देगी। एवोकाडो ने हाल के वर्षों में अपने बहुमुखी गुणों और स्वास्थ्य लाभों के कारण अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। इसकी मलाईदार बनावट और समृद्ध स्वाद के साथ, समझदार उपभोक्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो की अत्यधिक मांग की जाती है। ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो का आयात करके, आईजी इंटरनेशनल का उद्देश्य भारत में इस पौष्टिक सुपरफूड के लिए उपभोक्ताओं को एक बेहतर एवोकाडो अनुभव प्रदान करना है।

50 सालों से ताजा फल आयात कर रहा आईजील इंटरनेशनल

भारत में अग्रणी ताजा फल आयातक के रूप में आईजी इंटरनेशनल इस बाजार खंड में 50 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ है। एवोल्यूशन एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई एवोकाडो उत्पादक है जो स्थायी कृषि पद्धतियों और प्रीमियम एवोकाडो के उत्पादन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। असाधारण स्वाद और पोषण मूल्य प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ, एवोल्यूशन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले एवोकाडो का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।

-सभा स्थल लालपुर हवाई पट्टी से पकरिया गांव तक जुटाई जा रहीं सुविधाएं

मध्प्र की हर पंचायत में होगा प्रधानमंत्री की सभा का लाइव प्रसारण

सागर। जागत गांव हमार

शहडोल। जिले में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री की सभा का लाइव प्रसारण कराने की तैयारी हो रही है। सभा स्थल लालपुर हवाई पट्टी से लेकर पकरिया गांव तक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। पकरिया के जल्दीटोला में मोदी जनजातीय समुदाय के मुखिया से भी मिलेंगे। पकरिया में मोदी पेसा एक्ट की समितियों, लखपति बहनों, फुटबाल क्रांति से जुड़े खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। मंच से आयुष्मान, सिकलसेल एनीमिया कार्ड का वितरण करने के साथ सिकलसेल एनीमिया मिशन की घोषणा करेंगे।

जल्दीटोला के अर्जुन सिंह ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला तो वे अपने क्षेत्र में स्थाई रोजगार की मांग करेंगे। रिलायंस का प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र में है, लेकिन यहां लोगों को काम नहीं मिला। रिलायंस कंपनी मीथेन गैस निकालकर फूलपुर भेज रही है। वे यहां गैस आधारित कोई प्लांट लगाने की मांग करेंगे, जिससे कम पढ़े-लिखे लोगों को भी काम मिल सके।

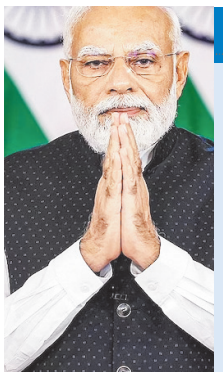

पकरिया पंचायत की स्थिति

» पकरिया ग्राम पंचायत की कुल आबादी 4700 है, जिसमें सर्वाधिक जनजातीय समुदाय के कोल, गोड़ और बैगा हैं। अनुसूचित जनजाति और यादव साहू, पटेल आदि शामिल हैं।

» 150 लोगों को पीएम आवास मिला है और 507 शौचालय बने हैं। ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस की श्रेणी में है।

» 300 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। सिकलसेल की जांच का शिविर अभी तक नहीं लगा है।

» पकरिया में जल्दीटोला, समदाटोला हैं। 150 लोग सरकारी जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें पट्टा नहीं मिला है।

सुविधाएं जुटाने में लगा प्रशासन

» एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो दो दिन पहले चालू किया गया है।

» 234 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और बाकी लोगों को दिलाने के लिए तीन दिन से सर्वे चल रहा है।

» आधे गांव में नलजल की सुविधा है। पहली बार गांव में स्ट्रीट लाइट से रोशन की तैयारी चल

साक्षात्कार | सवालों का सरपंच सीमा बाई ने बेबाकी से दिया जवाब

कृषि मंत्री के हरदा में घोषणाओं की बौछार, सुविधाओं का सूखा

भोपाल।

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा की जनपद पंचायत टिमरनी की पंचायतों के ग्रामीणों और किसनों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। यहां घोषणाओं के बाद भी रास्ता क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि डेढ़ किमी दूरी पर स्थित शांति धाम पहुंचने के लिए लोगों को आठ किमी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहां सबसे खराब हालत स्कूल, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की है। इसको लेकर जब महिला सरपंच सीमा बाई से सवाल किए तो उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...।

सवाल: आपकी पंचायत कुहीग्वाड़ी में नल जल योजना की क्या स्थिति है?

जवाब: हमारी पंचायत को नल जल योजना की मंजूरी मिल गई है। लेकिन दुर्भाग्य से एक साल भी काम शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर हम कई बार पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी गुहार चगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को द्वारा घोषणाएं तो बहुत कर दी जाती हैं, लेकिन विकास की सच्चाई कुछ और ही होती है।

सवाल: आपकी पंचायत कहां चल रही है? भवन की हालत कैसी है।

जवाब: मुझे यह बताने में शर्म आती है कि हमारे यहां पंचायत भवन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल ग्राम स्वराज भवन से पंचायत का संचालन किया जा रहा है। वो भी अब जर्जर हो गया है। कोई देखने वाला नहीं है। चार महीने पहले हम नए भवन के लिए टिमरनी जनपद में प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन मंजूरी नहीं प्रदान की जा रही है।

सवाल: आपकी पंचायत में पांच गांव हैं। सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है?

जवाब: यह बात सही है कि हमारी पंचायत कुहीग्वाड़ी में पांच गांव आते हैं। रही बात सामुदायिक भवन की तो वो है ही नहीं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इसको लेकर चार महीने पहले प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

सवाल: पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति है?

जवाब: यहां आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत बहुत खराब है। पंचायत में दो केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण एक केंद्र का संचालन किराये के भवन से किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि भवन ही नहीं है। इसका भी प्रस्ताव हम पांच महीने पहले महिला एवं बाल विकास विभाग को दे चुके हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ।

सवाल: कृषि मंत्री का गृह जिला है, यहां स्वास्थ्य केंद्र की हालत ठीक होगी?

जवाब: देखिए कहने के लिए तो प्रदेश के कृषि मंत्री का गृह जिला हरदा है। उसी में हमारी पंचायत भी आती है। लेकिन यहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं, उप-स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। लेकिन उसका भवन नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र से चल रहा है। यहां आने वाले मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों की परेशानी को देखते हुए हमने चार महीने पहले प्रस्ताव दिया है, लेकिन मंजूरी ही नहीं मिल रही है।

सवाल: आपकी पंचायत में सड़कों की कैसी हालत है?

जवाब: यहां सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सभी सड़कें जर्जर हो गई हैं। यहां तीन किमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है। जो किसी काम की नहीं है। हालांकि उसकी मरम्मत की स्वीकृति मिल गई है। काम कब शुरू होगा इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सवाल: कृषि मंत्री का क्षेत्र है तो बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होगी?

जवाब: आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी यहां सबसे खराब स्थिति बिजली की है। यहां किसान अपनी फसल तक समय पर नहीं सींच पाते हैं। कई जगह डीपियां जली पड़ी हैं। कोई देखने वाला नहीं है। कई जगह डीपी खुली पड़ी है। कभी किसी को करंट लग सकता है। लेकिन बिजली विभाग वाले कोई ध्यान ही नहीं देते हैं।

सवाल: पंचायत में राशन दुकान और गौशाला की क्या स्थिति है?

जवाब: हमारी पंचायत में राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। लेकिन वो भी किराये के भवन से। नए भवन के लिए हम पांच महीने पहले प्रस्ताव दिए थे, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। रही गौशाला की बात तो यहां मांग हो रही है। हम इसका भी प्रस्ताव देने जा रहे हैं। गौशाला बन जाने से किसानों की बड़ी समस्या दूर हो जाएगी।

सवाल: स्कूल किस कक्षा तक है? भवन की हालत ठीक है।

जवाब: हमारी पंचायत में मिडिल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इसका भवन काफी जर्जर हो गया है। करीब 60 साल पुराना है। वो भी कच्चा भवन है। जो कभी भी गिर सकता है। यहां एक नया स्कूल भवन नदी के किनारे बनाया गया था, लेकिन डूब में आने के कारण उसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने गिरा दिया है। अब नए भवन की स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन साल भर बाद भी पंचायत को राशि नहीं मिली है।

-हरी मटर से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन, हेल्दी सप्लीमेंट भी

नोटिफिकेशन के बाद जल्द बनेगी थाली का हिस्सा

एनआरसी-188 सेंट्रल जोन की पहली सोया वेजिटेबल

इंदौर।

मध्यप्रदेश सहित देशभर में कई सोया प्रोड्क्टस प्रचलन में हैं। अब बतौर सब्जी उपयोग की जा सकने वाली सोया वेजिटेबल की नई वैरायटी एनआरसी-188 भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा इसका सफल रिसर्च किया गया है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। एनआरसी-188 सेंट्रल जोन की पहली सोया वेजिटेबल है। इसमें मटर से चार गुना ज्यादा प्रोटीन है। नोटिफिकेशन के डेढ़ साल बाद यह सोया वेजिटेबल बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। लोग इसका उपयोग सब्जी या नाश्ते के रूप में कर सकेंगे। आईसीएआर की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट अनिता रानी ने बताया कि एनआरसी-188 सोयाबीन की अन्य वैरायटियों से अलग है। इसकी खूबी यह है कि इसकी हरी फली को उबालकर खा सकते हैं। यह दूसरे देशों में काफी प्रसिद्ध है लेकिन भारत में अब तक नहीं थी, खासकर सेंट्रल जोन में। यह सेंट्रल जोन की पहली वैरायटी है, जिसे हम सब्जी की तरह खा पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन इस साल के अंत तक हो सकता है।

यह हरी मटर की तरह

सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. विनीत कुमार ने बताया कि इस सोया वेजिटेबल का बीज गोल है। यह सेंट्रल जोन में पूरे मप्र, बुंदेलखंड और विदर्भ रीजन के लिए आईडेंटिफाई की गई है। इसकी खासियत यह है कि जब फली भर जाएगी यानी जब इसका छिलका हरा रहेगा, तब इसे तोड़ना होगा। यह हरी मटर की तरह है। हरी मटर रबी की फसल में आती है, लेकिन बारिश के सीजन में इस तरह की सोया वेजिटेबल की जरूरत बनी हुई है। जब इसके बीज भरे होंगे, तब इसे सब्जी की तरह उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए फली को दो से पांच मिनिट तक उबालना होगा।

12 से 15 फीसदी तक प्रोटीन

हरा छिलका और भरे दाने वाली फ्रेश सोया वेजिटेबल में हरी मटर की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। मटर में 3 फीसदी प्रोटीन मिलता है तो इसमें 12 से 15 फीसदी तक प्रोटीन है। इसमें सोयाबीन के अन्य हेल्दी सप्लीमेंट भी मिलेंगे। एनआरसी-188 की खासियत यह है कि यह सोयाबीन वेजिटेबल तो है ही, लेकिन जब यह मेच्योरिटी पर आती है तो इसका रंग आम सोयाबीन की तरह पीला हो जाता है। इसका उपयोग आम सोयाबीन की तरह भी किया जा सकता है।

70 दिन में तैयार

डॉ. विनीत कुमार ने कहा कि यह खरीफ की फसल है। जैसे बारिश में नॉर्मल सोयाबीन लगाते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। इसकी मेच्योरिटी अवधि 95 से 100 दिन की है लेकिन हरी फलियां 65 से 70 दिन में मिलने लगेंगी। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन होगा। डेढ़ से दो साल में यह सोया वेजिटेबल बाजार में मिलने लगेगी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)